संख्या- 358 /XXXVI-A-1/2020-104 एक (2)/2005

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल, सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल। GHZT 08-12-20

न्याय अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 🛷 दिसम्बर, 2020

विषय— मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष फौजदारी अपीलों / मुकदमा (वाद) में पैरवी करने हेतु न्यायमित्रों को देय पारिश्रमिक / फीस की दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0–3796/UHC/ Admin.B/IV-11/2010 दिनांक 21.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष फौजदारी अपीलों में पैरवी करने हेतु न्यायिनत्रों को देय पारिश्रमिक/फीस की दरों में वृद्धि किये जाने विषयक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष फौजदारी अपीलों में पैरवी करने हेतु न्यायमित्रों को देय पारिश्रमिक की दरों के निर्धारण विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–214/छत्तीस(1)/न्या0अनु0/2006 दिनांक 04.03.2006 में उल्लिखित दरों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

क्र0	शासनादेश दिनांक 04.03.2006 के	फीस दरों में की गयी वृद्धि
सं0	अनुसार देय फीस	_
1	खण्डपीठ में ₹ 5000/- प्रति	खण्डपीठ में ₹ 10,000 / - प्रति
	फौजदारी अपील	फौजदारी अपील / मुकदमा (वाद)
2	एकल खण्डपीठ में ₹ 3000/-	एकल खण्डपीठ में ₹ 7500 / — प्रति
	प्रति फौजदारी अपील	फौजदारी अपील / मुकदमा (वाद)

- 3— उक्त पारिश्रमिक की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि प्रति फौजदारी अपील / मुकदमा (वाद) में अन्तिम निस्तारण तक के लिये देय होगा।
- 4— उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2014—न्याय प्रशासन—00—भारित—102—उच्च न्यायालय—03—उच्च न्यायालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

400

क्रमशः....2

0/0

6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-830/XXVII(7)/2020 दिनांक 08.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय जिल्ली (प्रेम सिंह खिमाल) सचिव

## संख्या- 358(4)XXXVI-A-1/2020-104 एक (2)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
- 2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा अधिकरण, नैनीताल।
- 3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4. वित्त अनुभाग-7 / न्याय अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 5. एन०आई०सी० / गार्ड फाईल।

list

(सयन सिंह) अपर सचिव

0/6